कटनी पत्रिका

कैमोर . विजयराघवगढ़ . बहोरीबंद . स्लीमनाबाद . बाकल . ढीमरखेड़ा . बड़वारा . बरही . रीठी

एक्सक्लूसिव

दिल्ली की कंसलटेंसी कंपनी रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड को किया गया सर्वे के लिए नियुक्त, अब नहीं हो पाएगी टैक्स चोरी

बालमीक पाण्डेय
patrika.com

कटनी. शहर में हजारों लोग अभी भी ऐसे हैं जो टैक्स जमा नहीं कर रहे या चोरी कर रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि नगर निगम में या तो दर्ज नहीं हैं या फिर आवासीय में व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। अब कुछ दिनों बाद नगर निगम के खजाने में करोड़ों रुपए के राजस्व की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। कटनी नगर निगम ने जीआइएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर तैयार करने के लिए आरईपीएल की नियुक्ति की है। इसमें बहुउद्देश्यीय घरेलू सर्वे करने के लिए दिल्ली की कंसलटेंसी कंपनी रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरइपीएल) को नियुक्त किया है। बतादें कि जीआइएस सर्वे में बरती जा रही लापरवाही को पत्रिका ने उजागर किया, जिसके बाद अफसर हरकत में आए और अब सिस्टम को एक्टिव किया जा रहा है। आरपीईएल बड़े पैमाने पर जीआइएस बेस्ड बेस मैप बनाएगा, इसमें हाइ रेजोल्यूशन के सैटेलाइट डेटा और संबंधित क्षेत्र के ग्राउंड सर्वे का इस्तेमाल किया जाएगा। बेस मैप में सभी प्रमुख फिजिकल फीचर्स मौजूद होंगे। जैसे हर प्लॉट की बाउंड्री और निर्माण (ढांचा), यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (प्रॉपर्टी) की पहचान संख्या, ई नगर पालिका प्रॉपर्टी आईडी आदि।

डिमांड को करेगा अपग्रेड : जीआईए डेटाबेस के एकीकरण के साथ प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड को अपग्रेड करेगा। गैरस्थानिक डेटा बहुउद्देशीय होगा जिसका उपयोग इंजीनियरिंग, रेवेन्यू टैक्सेशन और टाउन प्लानिंग, जैसे नगर निगम के विभिन्न विभागों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। पारदर्शी तरीके से टैक्स का भुगतान होगा। टैक्स संग्रह का अतिरिक्त लाभ भी हासिल होगा। आरईपीएल के सीएमडी प्रदीप मिश्रा बताया कि टेक्नोलॉजी में इससे टैक्स कलेक्शन में बड़ा सुधार होगा।

इन टैक्सों में लाभ : आरईपीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. हरीश शर्मा ने बताया कि किसी जगह का एक परफेक्ट डेटा बेस होने से नगर निगम की योजना, प्रशासन और प्रबंधन में कई तरीकों से सुधार करके उसको और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन से सर्वे को ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित ढंग से करने में मदद मिलेगी।

अभी यह है स्थिति

- 47 हजार 974 अभी हैं शहर में प्रॉपर्टियां।
- 7 करोड़ 13 लाख रखा गया था राजस्व का लक्ष्य।
- 9 करोड़ 12 लाख रुपये हुई है राजस्व की वसूली।

जीआइएस बेस्ड बेस मैप बनेगा, इसमें हाइ रेजोल्यूशन के सैटेलाइट डेटा और संबंधित क्षेत्र के ग्राउंड सर्वे का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टैक्सेशन के लिए संपत्तियों की संख्या बढ़ेगी और करोड़ों का राजस्व भी।

जागेश्वर पाठक, नोडल अधिकारी राजस्व